eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

आर्थिक वृद्धि और जीवनस्तर में सुधार व भारतीय समाज में असमानता का अध्ययन (1947–2023)

डा0 मनोज कुमार अवस्थी[1]
[1]सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर, चित्रकूट, उ0प्र0

Received: 20 Jan 2024, Accepted: 28 Jan 2024, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2024

Abstract

यह शोध पत्र 1947 से 2023 तक भारत में आर्थिक वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार के बावजूद बढ़ती असमानता का विश्लेषण करता है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने योजनाबद्ध विकास मॉडल अपनाया, जिससे गरीबी में कमी आई और जीवन स्तर में सुधार हुआ। हालांकि, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद, उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद, आय और संपत्ति की असमानता में वृद्धि हुई। यह अध्ययन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से असमानता के रुझानों, उनके कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करता है, और समावेशी विकास के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

कीवर्ड्स– आर्थिक वृद्धि, जीवन स्तर, असमानता, भारत, 1947–2023, आय वितरण, संपत्ति असमानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक उदारीकरण, समावेशी विकास

Introduction

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही भारत ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक नई यात्रा शुरू की। एक कृषि प्रधान और औपनिवेशिक दोहन से जर्जर अर्थव्यवस्था को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदलने का लक्ष्य रखा गया। नेहरूवादी समाजवाद के मार्गदर्शन में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समावेशी विकास का प्रयास किया गया, जिसमें गरीबी हटाओ, रोजगार सृजन, और औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया। 1970 के दशक में गरीबी के खिलाफ सक्रिय सरकारी हस्तक्षेप, तथा 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों ने देश में तीव्र आर्थिक वृद्धि को गति दी। भारत ने आईटी, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक पहचान बनाई और वर्ष 2023 तक वह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। हालांकि, इस आर्थिक वृद्धि और जीवन स्तर में हुए समग्र सुधार के समानांतर, भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता की खाई निरंतर चौड़ी होती गई। उच्च आय वर्गों की आय और संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई, जबकि निम्न और मध्यम वर्गों की भागीदारी सीमित रही। आज भारत में शीर्ष 1 प्रतिशत के पास राष्ट्रीय आय और संपत्ति का एक अत्यधिक बड़ा हिस्सा है, जबकि निचले 50 प्रतिशत के लिए बुनियादी सुविधाएं अभी भी चुनौती बनी हुई हैं। इस असमानता का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर भी पड़ा है। असमानता की यह बढ़ती खाई केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि समाज की संरचना, अवसरों की समानता, और भविष्य की स्थिरता का प्रश्न बन चुकी है।

इस शोध में हम 1947 से 2023 तक के आर्थिक आंकड़ों, नीतिगत परिवर्तनों और सामाजिक प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि यह समझा जा सके कि कैसे आर्थिक वृद्धि के बावजूद समाज में असमानता बढ़ी और इसे किस प्रकार की नीतियों व सुधारों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

साहित्य समीक्षा– भारत में आर्थिक असमानता पर शोध कार्यों की एक सशक्त परंपरा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर आज तक असमानता को समझने हेतु अनेक अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और संस्थाओं द्वारा गहन अध्ययन किए गए हैं। यह खंड उन प्रमुख शोधों, रिपोर्टों और विचारों की समेकित समीक्षा प्रस्तुत करता है, जिन्होंने असमानता की प्रवृत्तियों, कारणों और परिणामों को उजागर किया है।

1. स्वतंत्रता के बाद असमानता पर प्रारंभिक अध्ययन– 1950 और 1960 के दशकों में असमानता का स्वरूप मुख्यतः ग्रामीण–शहरी विभाजन और जातीय–सामाजिक संरचना पर आधारित था। महालनोबिस मॉडल और पंचवर्षीय योजनाओं में समावेशी विकास की अवधारणा शामिल थी, किंतु व्यावहारिक स्तर पर संसाधनों का वितरण असमान रहा। के.एन. राज और पी.सी. महालनोबिस जैसे विद्वानों ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में भी वर्गीय अंतर और सामाजिक असमानता के बने रहने पर प्रकाश डाला।

2. उदारीकरण के बाद असमानता में तेज़ वृद्धि– 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) के बाद भारत ने वैश्विक बाज़ार के लिए अपने दरवाज़े खोले। इस चरण में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेज़ी आई, लेकिन साथ ही असमानता की गति भी बढ़ी। थॉमस पिकेटी और लुकास चौंसेल की रिपोर्ट "Indian Income Inequality, 1922–2023 (World Inequality Lab) ने यह स्पष्ट किया कि शीर्ष 01 प्रतिशत की आय हिस्सेदारी 1991 में लगभग 10 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 22.6 प्रतिशत हो गई, जबकि निचले 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी में गिरावट आई।

3. Oxfam India की रिपोर्टें– Oxfam India द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित रिपोर्टें, जैसे "Survival of the Richest" (2023), बताती हैं कि भारत में संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ रहा है। 2023 में भारत की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत शीर्ष 1 प्रतिशत के पास है, जो असमानता की गहराई को दर्शाता है। Oxfam का निष्कर्ष है कि वर्तमान विकास मॉडल ट्रिकल डाउन सिद्धांत पर आधारित है, जो वास्तविकता में काम नहीं कर रहा।

4. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSSO) और NITI Aayog की रिपोर्टें– NSSO द्वारा समय–समय पर प्रकाशित उपभोग व्यय सर्वेक्षण और बेरोज़गारी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि निम्न और मध्य वर्गों की क्रय शक्ति स्थिर रही है, जबकि महँगाई और स्वास्थ्य–शिक्षा व्यय में तेज़ वृद्धि हुई है। नीति आयोग (NITI Aayog) की रिपोर्टें मानती हैं कि "Inclusive Development Index" में भारत की स्थिति औसत से कम रही है।

5. अंतरराष्ट्रीय तुलना एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण– United Nations Development Programme (UNDP) और World Bank ने भी भारत की असमानता को वैश्विक स्तर पर विश्लेषित किया है। UNDP की Human Development Report (2022) में भारत का HDI रैंकिंग 132वीं थी, जो दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि मानव विकास में परिवर्तित नहीं हो रही है।

अनेक समाजशास्त्री यह भी तर्क करते हैं कि जातीय, लिंग और क्षेत्रीय असमानताएं केवल आर्थिक न होकर संरचनात्मक हैं, जो संविधान में समानता के सिद्धांत को चुनौती देती हैं।

शोध पद्धति– इस शोध पत्र में 1947 से 2023 तक के समयावधि में भारत की आर्थिक वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार और असमानता के बदलते स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। चूंकि यह एक ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और सांख्यिकीय अध्ययन है, अतः यह पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) पर आधारित है। अध्ययन हेतु निम्नलिखित पद्धतियों का उपयोग किया गया है–

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

1. अनुसंधान का स्वरूप– यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) प्रकृति का है। इसमें समय–श्रृंखला (time-series) डेटा के माध्यम से विभिन्न दशकों में असमानता, आर्थिक वृद्धि और जीवन स्तर के संकेतकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

2. आंकड़ा संग्रहण (Data Collection)– अध्ययन के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से द्वितीयक डेटा संग्रहित किया गया है। मुख्य स्रोतों में शामिल हैं, भारत सरकार की रिपोर्टें, योजना आयोग, नीति आयोग, जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO), आर्थिक सर्वेक्षण। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ – World Bank, IMF, UNDP, World Inequality Lab, Oxfam.

शोध पत्र और अकादमिक प्रकाशन, थॉमस पिकेटी, लुकास चौंसेल, अमर्त्य सेन, और अभिजीत बनर्जी के शोध।

3. अध्ययन के प्रमुख संकेतक (Key Indicators)– इस अध्ययन में जिन प्रमुख सामाजिक–आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण किया गया है, वे निम्नलिखित हैं–

आर्थिक वृद्धि संकेतक – GDP] GDP per capita, सेवा और औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर।

असमानता संकेतक – Gini coefficient, शीर्ष 1 प्रतिशत/10 प्रतिशत आय व संपत्ति हिस्सेदारी, Palma Ratio।

जीवन स्तर संकेतक, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, गरीबी दर, स्वास्थ्य व शिक्षा पर खर्च, उपभोग व्यय।

4. डाटा विश्लेषण के उपकरण (Tools of Analysis)– सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistical Tools) – प्रतिशत परिवर्तन, औसत, विचलन।

दृश्य प्रस्तुति (Graphical Representation)– रेखा चित्र (line graphs), स्तंभ चित्र (bar graphs), तालिकाएं (tables)।

सहसंबंध और प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis - Correlation)– यह जांचने हेतु कि आय वृद्धि और असमानता में कैसा संबंध रहा है।

5. समय सीमा (Time Frame)– शोध का कालखंड स्वतंत्रता प्राप्ति (1947) से लेकर हालिया वर्ष 2023 तक का है, जिसे तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है–

1950–1990 योजनावधि समाजवाद और राज्य–नियंत्रित अर्थव्यवस्था।
1991–2010 आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण।
2011–2023 उच्च आर्थिक वृद्धि, डिजिटलीकरण, और नव–लोक कल्याणकारी योजनाएँ।

यह पद्धति इस शोध को तर्कसंगत, तुलनात्मक और गहराई से विश्लेषणात्मक बनाने में सहायक है, जिससे निष्कर्ष न केवल आंकड़ों पर आधारित हों, बल्कि नीति–निर्माण में भी उपयोगी सिद्ध हों।

डेटा विश्लेषण (Data Analysis)– इस खंड में भारत की आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में सुधार, और सामाजिक–आर्थिक असमानता से संबंधित विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण को तीन प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया गया है–

चरण 1, 1950–1990 (नियोजित विकास)

चरण 2 1991–2010 (उदारीकरण)

चरण 3 2011–2023 (तेज वृद्धि और डिजिटलीकरण)

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

तालिका–01

भारत की GDP वृद्धि दर (1950–2023)		
क्र. सं.	कालखंड	औसत वार्षिक GDP वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	1950–1990	3.5 प्रतिशत (हिंदू दर)
2	1991–2010	6.5 प्रतिशत
3	2011–2023	7.2 प्रतिशत

विश्लेषण– उदारीकरण के बाद GDP वृद्धि दर में स्पष्ट तेज़ी देखी गई, विशेष रूप से सेवा और तकनीक क्षेत्रों में। हालाँकि, यह वृद्धि सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँची।

तालिका–02

गिनी गुणांक (Gini Coefficient) द्वारा असमानता माप				
क्र. सं.	वर्ष	ग्रामीण गिनी	शहरी गिनी	कुल भारत
	1951	0.30	0.34	0.32
	1991	0.32	0.38	0.36
	2011	0.37	0.42	0.40
	2023	0.39	0.47	0.43

विश्लेषण– शहरी क्षेत्रों में असमानता अधिक तीव्र रही है, जो दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि मुख्यतः उच्च आय वर्ग को लाभ पहुँचा रही है।

तालिका–03

आय और संपत्ति में शीर्ष 1 प्रतिशत की हिस्सेदारी			
क्र. सं.	वर्ष	शीर्ष 1 प्रतिशत की आय हिस्सेदारी (प्रतिशत)	शीर्ष 1 प्रतिशत की संपत्ति हिस्सेदारी (प्रतिशत)
1	1980	6.1 प्रतिशत	9.8 प्रतिशत
2	2000	12.5 प्रतिशत	20.3 प्रतिशत
3	2020	21.7 प्रतिशत	39.5 प्रतिशत
4	2023	22.6 प्रतिशत	40.1 प्रतिशत

विश्लेषण– थॉमस पिकेटी व चौंसेल के अनुसार यह वैश्विक स्तर पर असमानता के सबसे अधिक स्तरों में से एक है। संपत्ति का केंद्रीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है।

तालिका–04

राज्यवार असमानता (2020–2023) अंतर–राज्यीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) (₹ लाख करोड़ में)

क्रम	राज्य	2020–21 (अनुमानित)	2021–22 (अनुमानित)	2022–23 (अनुमानित)	वार्षिक औसत वृद्धि (प्रतिशत)
1	महाराष्ट्र	28.18	32.24	36.73	14.5:
2	तमिलनाडु	20.40	23.36	27.12	15.0:
3	उत्तर प्रदेश	17.05	19.22	21.35	11.5:
4	गुजरात	16.55	18.73	21.11	13.0:
5	कर्नाटक	17.25	19.45	22.80	14.0:
6	पश्चिम बंगाल	13.10	14.90	17.25	13.2:
7	राजस्थान	10.05	11.35	13.05	13.5:
8	आंध्र प्रदेश	9.90	11.40	13.10	15.1:
9	मध्य प्रदेश	10.15	11.85	13.55	14.0:
10	बिहार	7.80	8.90	10.20	13.5:

विश्लेषण– राज्यवार विकास अत्यंत असंतुलित है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध हैं, जबकि बिहार, यूपी जैसे बड़े राज्य अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं।

सामाजिक असमानता : जाति व लिंग के आधार पर– SC@ST वर्गों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति में भागीदारी औसत से कम रही है। महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में लगभग 20–30 प्रतिशत कम है। कार्यबल में महिला भागीदारी 2023 में 20 प्रतिशत थी, जो वैश्विक औसत (47 प्रतिशत) से बहुत कम है।

भारत में आर्थिक वृद्धि के सकारात्मक संकेतकों के बावजूद सामाजिक–आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। असमानता केवल आय या संपत्ति तक सीमित नहीं, बल्कि अवसरों, सेवाओं और गरिमा तक फैली है। डिजिटलीकरण और योजनाओं के बावजूद, अगर नीति–निर्माण में समावेशिता और न्याय पर बल नहीं दिया गया, तो असमानता राष्ट्र की दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता को चुनौती दे सकती है।

आर्थिक वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार के बीच एक जटिल संबंध होता है, विशेषतः जब उस समाज में ऐतिहासिक, सामाजिक और संरचनात्मक असमानताएं गहराई से जमी हों। भारत में 1947 से 2023 तक

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

की आर्थिक यात्रा के दौरान यह देखा गया है कि जहाँ एक ओर सकल घरेलू उत्पाद (GDP), जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और तकनीकी प्रगति के सूचकांक निरंतर ऊपर गए हैं, वहीं दूसरी ओर आय, संपत्ति, और अवसरों की असमानता भी कई गुना बढ़ी है।

1. आर्थिक वृद्धि का असमान वितरण– उदारीकरण (1991) के बाद भारत ने विश्व स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना शुरू किया। किंतु यह वृद्धि 'Inclusive Growth' के बजाय 'Exclusive Growth' सिद्ध हुई। डेटा से स्पष्ट है कि ळक्च् की वृद्धि दर में तेज़ी के बावजूद केवल उच्च आय वर्ग ने इसका बड़ा लाभ प्राप्त किया। शीर्ष 1 प्रतिशत वर्ग की संपत्ति और आय में चार गुना वृद्धि हुई, जबकि निचले 50 प्रतिशत वर्ग की वास्तविक आय में बहुत कम परिवर्तन आया। विकास के आँकड़े चमकदार हैं, लेकिन उनके नीचे छिपी असमानता की दरारें और गहरी होती जा रही हैं।

2. क्षेत्रीय विषमता– भारत में राज्यवार आर्थिक प्रदर्शन में भी भारी अंतर पाया गया। पश्चिमी और दक्षिणी राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, और केरल अधिक समृद्ध हुए हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य अपेक्षाकृत पिछड़े रहे। यह अंतर–राज्यीय असमानता न केवल आर्थिक असंतुलन को बढ़ावा देती है, बल्कि सामाजिक असंतोष और प्रवास की समस्याओं को भी जन्म देती है।

3. सामाजिक संरचनात्मक असमानता–

(क) जातीय असमानता– SC, ST और OBC वर्गों के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसर सीमित रहे हैं। भले ही आरक्षण नीतियों ने कुछ हद तक भागीदारी बढ़ाई हो, फिर भी उनके आय और संपत्ति के स्तर में भारी अंतर बना हुआ है।

(ख) लिंग असमानता– महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी आज भी 20 प्रतिशत से नीचे है। घरेलू श्रम, लैंगिक वेतन अंतर, और शिक्षा में असमानता महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित करती है। असमानता केवल धन का अंतर नहीं, बल्कि किसे अवसर मिलता है और किसे नहीं, का प्रश्न है।

4. जीवन स्तर में सुधार, असमान प्रगति– हालाँकि औसत जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, और गरीबी दर में सुधार हुआ है, लेकिन यह औसत आंकड़े हैं, जो समाज के उच्च वर्ग द्वारा ऊपर खींचे गए हैं। निचले वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों, और विशेषकर महिलाओं व दलितों के लिए ये सुधार अपेक्षाकृत धीमे और असमान रहे हैं।

5. नीति असमानता पर मौन रही है– भारत की अधिकांश आर्थिक नीतियाँ उत्पादन और निवेश पर केंद्रित रही हैं, उपभोग और वितरण पर नहीं। Redistributive policies, जैसे संपत्ति कर, विरासत कर, या सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, बहुत सीमित रही हैं। उदाहरण के लिए, मनरेगा जैसी योजनाएँ अल्पकालिक राहत देती हैं, लेकिन दीर्घकालिक समानता की दिशा में निर्णायक परिवर्तन नहीं कर पातीं।

6. महामारी (COVID-19) ने असमानता को और गहरा किया– 2020–2021 की महामारी ने गरीब और असंगठित क्षेत्र के लोगों पर विनाशकारी प्रभाव डाला। जहाँ अमीर वर्ग डिजिटल तकनीक और घर से काम कर आर्थिक रूप से सुरक्षित रहा, वहीं करोड़ों मज़दूरों की आजीविका समाप्त हो गई।

भारत की आर्थिक वृद्धि ऊर्ध्वमुखी (top-heavy) रही है, यानी शीर्ष वर्ग की ओर केंद्रित। जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने वाली नीतियाँ नहीं अपनाई जातीं, तब तक जीवन स्तर में हुए सुधार केवल आँकड़ों की चकाचौंध तक सीमित रहेंगे।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

निष्कर्ष– 1947 से 2023 तक भारत ने एक लंबी और जटिल आर्थिक यात्रा तय की है, स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित समाजवाद से लेकर आज के उदारीकृत, बाज़ार–आधारित मॉडल तक। इस दौरान देश ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की, GDP वृद्धि, आधारभूत संरचना, तकनीकी नवाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। परंतु इस आर्थिक वृद्धि की वास्तविकता बहुत असमान रही है। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

आर्थिक वृद्धि असमान रही है – GDP बढ़ा, पर उसका बड़ा लाभ सीमित वर्गों तक ही गया। आय और संपत्ति की विषमता तेजी से बढ़ी है, विशेष रूप से 1991 के बाद में। जीवन स्तर में सुधार हुआ, लेकिन यह सभी सामाजिक समूहों के लिए समान नहीं रहा है। जाति, लिंग, और क्षेत्रीय असमानता आज भी गहराई से समाज में मौजूद हैं। नीति निर्माण में वितरणात्मक न्याय की अनुपस्थिति ने असमानता को और मजबूत किया।

इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत की आर्थिक प्रगति का वर्तमान मॉडल सतत (sustainable) और समावेशी (inclusive) नहीं है। यदि असमानता की खाई निरंतर बढ़ती रही, तो सामाजिक स्थिरता, लोकतांत्रिक संतुलन, और मानव विकास पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकते हैं।

सिफारिशें (Recommendations)–

नीचे कुछ नीतिगत और सामाजिक उपाय दिए गए हैं, जो भारत को अधिक समावेशी और न्यायसंगत विकास की ओर ले जा सकते हैं–

1. वितरण–आधारित नीति निर्माण अर्थात उच्च आय/संपत्ति वर्ग पर प्रगतिशील कर प्रणाली को और मज़बूत किया जाए। विरासत कर (Inheritance Tax) जैसे उपायों पर पुनर्विचार हो। संपत्ति कर और पूँजी लाभ कर को अधिक न्यायसंगत बनाया जाए।

2. सार्वजनिक सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में समान और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ सुनिश्चित हों। प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाए।

3. सामाजिक सुरक्षा का विस्तार अर्थात मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष और पेंशन योजनाओं को व्यापक बनाया जाए।

4. लिंग और जाति आधारित समानता अर्थात महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी बढ़ाने हेतु सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व लाभ, और लचीलापन प्रदान किया जाए। SC@ST@OBC के लिए शिक्षा और उद्यमिता में सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) को सशक्त किया जाए।

5. डिजिटल समावेशन अर्थात डिजिटलीकरण के युग में ग्रामीण और पिछड़े वर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट पहुँच और डिजिटल सेवाओं का सशक्तीकरण आवश्यक है।

6. राज्यवार विकास संतुलन अर्थात पिछड़े राज्यों के लिए विशेष राजकोषीय सहायता और औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना की जाए। अंतर–राज्यीय संसाधन विभाजन में न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाया जाए।

विकास केवल GDP के आँकड़ों में नहीं मापा जा सकता, बल्कि इस बात में कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक अवसर, गरिमा और समृद्धि कितनी पहुँच पाई है। भारत को अब सशक्त भारत के विचार

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

से आगे बढ़कर समान भारत की ओर बढ़ना होगा, जहाँ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय साथ–साथ चलें।

भारत ने पिछले सात दशकों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, असमानता की बढ़ती खाई को पाटने के लिए समावेशी नीतियों की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर तथा प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाकर असमानता को कम किया जा सकता है।

संदर्भ सूची–

1. World Bank (2023)– India: Country Overview- www-worldbank-org-en.country.india
2. Piketty, T-, & Chancel, L- (2017) – Indian Income Inequality, 1922-2015: From British Raj to Billionaire Raj- WID-world Working Paper-
3. National Sample Survey Office (NSSO) – Reports on Employment] Consumption & Expenditure (Various Rounds)-
4. Government of India (1951–2023) – Five Year Plans & Economic Surveys-
5. Oxfam India (2023) – Survival of the Richest: The India Supplement-
6. Human Development Report – UNDP (2021) – India Human Development IndeÛ Report-
7. Economic Survey of India (Various Years) – Ministry of Finance] Government of India-
8. NITI Aayog (2020) – SDG India Index & Dashboard-
9. International Labour Organization (ILO) – Reports on gender inequality and informal labour in India-
10. Planning Commission & NITI Aayog (2011 2019) – Reports on poverty estimation in India-
11. Census of India (1951, 2001, 2011) – Data on literacy- life expectancy] population demographics-
12. Thomas, P- (2020) – Capital and Ideology- Harvard University Press-